

प्रेषक,

डा० निधि पाण्डेय,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तराखण्ड,
उद्यान भवन, चौबटिया-रानीखेत।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग:-1

देहरादून: दिनांक 02 फरवरी, 2015

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-00-आयोजनागत-119-बागवानी और सब्जियों की फसलें-02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि का प्रस्ताव (राज्य सैक्टर)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-638/1-1(102)/2014-15, दिनांक 2 दिसम्बर, 2014 एवं वित्त अनुभाग-1 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-1055/XXVII(1)/2014, दिनांक-30 दिसम्बर 2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-00 आयोजनागत-119-बागवानी और सब्जियों की फसलें 02-स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत योजना 0208-न्युनवर्गी पालन(राज्य सैक्टर) में ₹0 7,26,000.00 एवं योजना 0216-उद्यानों की घेरबाड़ की योजना में ₹0 2,50,000.00 कुल ₹9,76,000.00(₹0 नौ लाख छिहत्तर हजार मात्र) की योजनान्तर्गत अवशेष धनराशि सलग्न विवरणानुसार उपमदों में कम्प्यूटर आई0डी0 सहित आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) इस धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यों हेतु स्वीकृत परिव्यय सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।
- (2) उक्त व्यय करते समय वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-318/XXVII(1)/2014, दिनांक-18 मार्च, 2013 के द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत अन्य दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- (3) धनराशि व्यय करते समय प्रक्योरमेन्ट रूल्स, 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1(वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय सूचना प्रौद्योगिकी (I.T.) विभाग के शासनादेशों/दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
- (4) अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग त्रैमास के आधार पर शासन को उपलब्ध करायी जाय, जिससे राज्य स्तर पर कैशप्लो निर्धारित किए जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।
- (5) निर्माण कार्यों के लागत व वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कड़ी कार्यवाही व सघन अनुश्रवण किया जायेगा एवं इस हेतु बजट मैनुअल 2012 के सम्बन्धित प्रस्तारों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा सम्बन्धित योजनाओं में वृहत निर्माण एवं लघु निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय। यदि किसी निर्माण कार्य में किन्हीं कारणोंवश कार्य प्रारम्भ नहीं हुए तो उनकी स्वीकृति निरस्त करते हुए आवश्यकतानुसार उन कार्यों के सम्बन्ध में नये आगणन के आधार पर बजट उपलब्धता के दृष्टिगत नये सिर से विचार किया जाय। प्रत्येक निर्माणाधीन कार्य के सम्बन्ध में

क्रमशः.....2

Cm. 10

वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 15.12.08 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 किया जायेगा।

- (6) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो वहाँ व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- (7) व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है, साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।
- (8) आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण सम्बन्धित प्रपत्र में प्रत्येक माह वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय।
- (9) योजनावार व्यय की सूचना सम्बन्धित प्रपत्र पर प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय तथा धनराशि का आहरण/व्यय एकमुश्त न करके परिव्यय की सीमान्तर्गत वास्तविक आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
- (10) योजनावार स्वीकृत धनराशि का व्यय सम्बन्धित योजना के संगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही की जायेगी। किसी भी दशा में संगत दिशा-निर्देशों से इतर कार्यवाही नहीं की जायेगी।
- (11) उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि विभाग के नियंत्रणाधीन सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को तात्कालिकता से अवमुक्त कर दी जाय, ताकि फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।
- (12) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-30 के अन्तर्गत उपराक्त योजनान्तर्गत सम्बन्धित लखाशेषक अनुसार सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नाम डाला जायेगा।
- (13) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग करते समय मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जाय तथा समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाय।
- (14) यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1055/XXVII(1)/2014, दिनांक-30 दिसम्बर 2014 के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीया,

(डा० निधि पाण्डेय)
प्रभारी सचिव।

संख्या-2323/XVI(1)/15/7(5)/14, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भोटर्स बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
- 2- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
- 3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 4- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5- वित्त अनुभाग-4/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 6- बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 7- राज्य योजना आयोग, देहरादून, उत्तराखण्ड।
- ✓ 8- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
- 9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
उप सचिव।